राष्ट्रीय दैनिक

प्रातःकिरण

दिल्ली एवं पटना से प्रकाशित

हर खबर पर पकड़

/Pratahkiran /Pratahkiran /Pratahkiran

10 अब आईफोन बनाएगी टाटा, ऐपल सहस्वलायर विस्ट्रॉन से समेटा ...

भाजपा के लिए टेंशन बन जाएगा त्रिपुरा? सीएम साहा से नाराज बड़े ... 12

वर्ष : 14 | अंक : 14 | नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 मई, 2023 | विक्रम संवत् 2080 | पेज : 12 | मूल्य ₹ : 03.00 | www.pratahkiran.com

मौसम अधिकतम तापमान 45°C न्यूनतम तापमान 24.0°C

हां 30%
नहीं 50%
कह नहीं सकते 10%

बाजार

सोना 59,995

चांदी 72,500

सैंसेक्स 57,635

निफ्टी 16,986

उर्वरकों की आपूर्ति हेतु जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से होगा अनुपालन : सर्वजीत

- कृषि मंत्री ने किया राज्यस्तरीय खरीफ कर्मशाला का उद्घाटन
- किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता

प्रातः किरण संवाददाता

पटना। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने गुरूवार को बामेती सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय खरीफ कर्मशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि गत वर्ष से कृषि विभाग द्वारा विभिन्न फसलों के आच्छादन का आकलन पंचायत स्तर से कृषि समन्वयकों द्वारा विहान ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर अंतिम रूप दिया जाता है। इस वर्ष धान का कुल आच्छादन 35.50 लाख हेक्टेयर, मक्का का 3.35 लाख हेक्टेयर, अरहर का 0.59 लाख हेक्टेयर, मूंग का 0.23 लाख हेक्टेयर जबकि मोटे अनाज में बाजरा का 0.075 लाख हेक्टेयर, ज्वार का 0.06 लाख हेक्टेयर तथा मडुआ का 0.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान का निर्धारित आच्छादन क्षेत्र के अनुसार 3.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिचड़ा गिराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि में बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में खरीफ मौसम में किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अन्तर्गत किसानों को 5085.36 क्विंटल धान का बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य में अधिक उपजशील नवीनतम प्रभेदों के आधार बीज का सुदृढ़ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर उर्वरकों की आपूर्ति कराने तथा उचित मूल्य पर उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

मंत्री ने बताया कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजनांतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 19595 एकड़ में जैविक खेती करने हेतु किसानों को जैविक उत्पादन के लिए 6,500 रुपए प्रति एकड़ की दर से अग्रिम अनुदान दिया जायेगा। एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए इस अनुदान का लाभ ले सकता है। हरी खाद योजना के अंतर्गत राज्य में गरमा मौसम में 28,000 है क्षेत्र के लिए किसानों के बीच 90 प्रतिशत अनुदान पर ढैंचा बीज वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन हेतु भूमि संरक्षण निदेशालय तथा विहार जलछाजन विकास समिति द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। सात निश्चय-2 योजना के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए छोटी-छोटी नदियों से निकलने वाले नाले पर 30 फीट तक का 242 पक्का चेक डैम का निर्माण कराया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जलछाजन क्षेत्र में स्थित 5205 जल संग्रहण संरचनाओं का प्रबंधन किया जायेगा, जिस पर 141.59 करोड़ रुपए व्यय सम्भावित है। श्री कुमार ने कहा कि खरीफ मौसम में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य में 4315 है में वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने के लिए फलदार वृक्षों का क्षेत्र विस्तार किया जायेगा। साथ ही, विशेष उद्यानिक फसल योजना के अंतर्गत 100 है में चाय की खेती के क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को 4.94 लाख/है० इकाई लागत का 50 प्रतिशत सहायतानुदान दिया जायेगा। कार्यक्रम में कृषि विभाग के विशेष सचिव रवीन्द्रनाथ राय, कृषि निदेशक डॉ आलोक रंजन घोष, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, निदेशक पीपीएम धनंजयपति त्रिपाठी, निदेशक भूमि संरक्षण वैंकटेश नारायण सिंह, निदेशक बसोका सुनील कुमार पंकज, निदेशक बामेती आभांशु सी जैन सहित मुख्यालय एवं क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी तथा वैज्ञानिकगण उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

प्रवीण सूद ने सीबीआई के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

नईदिल्ली। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया। वह दो साल तक इस पद पर रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अपने अंतिम कार्यदिवस के दिन निवर्तमान निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने सूद को यहां सीबीआई मुख्यालय में एजेंसी का प्रभार सौंपा। सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। वह कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक थे और जायसवाल के बाद देश के शीर्ष वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सूद के नाम को मंजूरी दी गई थी।

ट्रक-टैंपो की टक्कर में 5 लोगों की मौत

मुंबई। हिंगोली जिले में हिंगोली-वाहेड हाइवे पर मालेगांव के पास गुरुवार तड़के चार बजे ट्रक- टैंपो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को कलमनुरी स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार बीती रात टैंपो चालक कलमनुरी से भेड़ लादकर नांदेड़ की ओर जा रहा था। तड़के चार बजे टैंपो चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सामने जा रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंपो के परखच्चे उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलने पर कलमनुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक बैजनाथ मुंडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया। इस घटना में मृतकों की पहचान सलमान अली मौला अली, सत्यनारायण बलाई, लालू मीना, कादीर मेवाती, आलम अली के रूप में हुई है। इनमें से एक राजस्थान के और चार लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। दुर्घटना में एक घायल को कलमनुरी स्थित जिला अस्पताल से नांदेड़ शासकीय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस भीषण हादसे में टैंपो में सवार 150 भेड़ों की भी मौत हो गई है।

तंबू पर पेड़ गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बृहस्पतिवार सुबह पीड़ा का पेड़ एक तंबू पर गिरने से घुमंतू समुदाय के एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना केशवन में भालना वन क्षेत्र में हुई। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ कर तंबू पर गिर गया। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील पोशवाल ने कहा, वन्यीय क्षेत्र में खानाबदोश परिवार द्वारा लगाए गए तंबू पर पीड़ा का पेड़ गिर गया। आज तड़के इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह परिवार अपनी भेड़-बकरियों के साथ दादन की ओर जा रहा था लेकिन भारी बारिश के कारण उन्हें भालना के जंगल में रुकना पड़ा। किश्तवाड़ के उपायुक्त देवेंद्र यादव ने बताया कि तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यादव ने कहा, पुलिस का एक दल तुरंत मौके पर पहुंचा और बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि शवों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है।

बिहार राज्य आवास बोर्ड : पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नेपाली नगर वासियों को बड़ी राहत

मकान तोड़ने पर लगाई रोक, मुआवजा देने का दिया आदेश

नेपाली नगर में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाइयां

प्रातः किरण

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने गुरूवार को बिहार राज्य आवास बोर्ड की राजीव नगर स्थित जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर गुरुवार को फैसला सुनाया है। आवास बोर्ड और प्रशासन की ओर से लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच ने तोड़े गए मकान के बदले पांच-पांच लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही 2018 के पहले बने हुए मकानों को सेटलमेंट करने का निर्देश भी जारी किया है। कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इलाके के तोड़े गए मकान के बदले लोगों को 5 –5 लाख रुपया मुआवजा देने का निर्देश दिया है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि नेपाली नगर में प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर पहले वहां रह रहे लोगों को नोटिस दिया ना अपील करने का वक्त दिया। जिन घरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है वो अतिक्रमणकारी नहीं हैं। नेपाली नगर के लोगों के लिए ही दीघा स्पेशल सेटलमेंट एक्ट और स्कीम बनी थी। राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। इस वजह से हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। मालूम हो कि, 21 जुलाई 2022 को जिला प्रशासन की टीम नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। जिला प्रशासन की टीम का कहना था कि लोगों को नोटिस दे दिया गया है। इसके बाद भी लोगअवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे हैं। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। जिसके बाद वहां से लोगों से पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध किया था। इस दौरान पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प भी हुई थी। कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस पूरे मामले को लेकर राजीव नगर थाने में दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए थे इधर, प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और नए निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था। इसके साथ ही कहा था कि पूरे इलाके में बिजली-पानी बहाल की जाए। अब इस पूरे मामले में 10 महीने बाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। इसके साथ ही कोर्ट से इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट मांगी गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नेपाली नगर इलाके में जश्न का माहौल है। लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ की और भगवान को 151 किलो लड्डू चढ़ाया। भगवान हनुमान को लड्डू का भोग लगाने के बाद इलाके में महाभंडारे का भी आयोजन किया। जिसमें 10 हजार से अधिक लोगों के भोजन की व्यवस्था की गयी है।

झारखंड के आदिवासी बाकी राज्यों के मुकाबले सशक्त हैं : मुर्मू

प्रातः किरण/एजेंसी

रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झूंरी में आयोजित स्वयं सहायता महिला सम्मेलन में जोहार से अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज में पैदा होना कोई बुराई नहीं है और मैं इसका उदाहरण हूं। राष्ट्रपति ने आज कहा कि मैं ओड़िशा की हूं लेकिन खून झारखंड का है। मेरी दादी मंत्री जोया माझी के गांव की थी। जब छोटी थी तो मेरी दादी मुझे 5 किमी दूर महुआ चुनने ले जाती थी। जब खाना नहीं मिलता तो हमलोग महुआ उबालकर खाते थे। तब उसका और इस्तेमाल पता नहीं था लेकिन उसी महुआ से केक सहित कई उत्पाद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं केवल धान की खेती पर निर्भर नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं कई राज्यों में घूमी हूं। महिलाओं से मिलती हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी बाकी राज्यों के मुकाबले सशक्त है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अब प्रगति पथ पर हैं और मैं इस बात से काफी खुश हूं। मुख्यमंत्री के संबोधन का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी शायद उतना नहीं हुआ इसलिए सीएम हेमंत सोरेन दुखी थे लेकिन मैं खुश हूं। झारखंड में एक बार को छोड़कर हर बार कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री बना। झारखंड 28 विधायक आदिवासी हैं।

ईपीएफओ में सात लाख अधिक कर्मचारी किये गये शामिल

नई दिल्ली। मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सात लाख से अधिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 13 लाख से अधिक और राष्ट्रीय पेंशन योजना में 99 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल किये गये हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को यहां जारी आंकड़ों में बताया कि मार्च 2023 में ईपीएफओ में कुल सात लाख 57 हजार 192 कर्मचारी जोड़े गये हैं। इनमें से पांच लाख 67 हजार 149 पुरुष और एक लाख 90 हजार 630 महिलायें हैं। अन्य श्रेणी में आठ कर्मचारी हैं और पांच के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सितंबर 2017 से मार्च 2023 तक छह करोड़ 43 लाख 54 हजार 850 कर्मचारी ईपीएफओ में जोड़े गये हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) में मार्च 2023 कुल 13 लाख नौ हजार 864 कर्मचारी शामिल हुए हैं। इनमें से 10 लाख 36 हजार 92 पुरुष और दो लाख 72 हजार 846 महिलायें हैं। अन्य श्रेणी में 26 कर्मचारी शामिल हैं।

आईएनएस विक्रांत पर मिग-29के फाइटर जेट ने की नाइट लैंडिंग

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। भारतीय नौसेना ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। नौसेना के आईएनएस विक्रांत पर पहले मिग–29के फाइटर जेट ने नाइट लैंडिंग की है। नौसेना का कहना है कि यह रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नौसेना के मुताबिक, भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत युद्धपोत पर मिग–29के को रात में सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई है। नौसेना की यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत की ओर बड़ा कदम है। गौरतलब है कि इससे पहले तेजस विमान के नौसैनिक वर्जन ने आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। हालांकि, मिग–29के लैंडिंग इसके मुकाबले कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि जहां तेजस विमान की लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी वहीं मिग–29के की लैंडिंग रात को हुई है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने कामोव 31 हेलीकॉप्टर को भी 28 मार्च को आईएनएस विक्रांत पर उतारा था। भारतीय नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण के दौरान स्वदेशी प्रकाश सहायक उपकरण और शिपबोर्ने सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो कि पूरी तरह सफल सिद्ध हुए। विक्रांता अपने आप में भारतीय नौसेना का एक बेहद महत्वपूर्ण जहाज है। इसे भारत के कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। आई एन एस विक्रांत की ऊंचाई यह 59 मीटर है। नौसेना के मुताबिक उनके इस युद्धपोत की थीम 62 मीटर की है। आई एन एस विक्रांत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इस युद्धपोत की एक खासियत यह भी है कि इसमें नौसेना की महिला अधिकारियों के लिए अलग केबिन हैं। भारतीय नौसेना की इस स्वदेशी युद्धपोत ने तमाम चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहां आईसीयू जैसी महत्वपूर्ण मेडिकल सर्विस भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ इस युद्धपोत में प्रयोगशाला में भी हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत का कुल वजन करीब 40 हजार टन है। यही कारण है कि नौसेना का यह युद्धपोत अन्य एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत विशाल है।

दोहरे खतरे को देखते हुए सेना के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी जरूरी : राजनाथ

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि सीमाओं पर दोहरे खतरे को देखते हुए सेना का उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस होना जरूरी है तथा इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और शैक्षणिक जगत यानी एकेडेमिया के बीच तालमेल तथा साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री सिंह ने आज यहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन –शैक्षणिक जगत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डीआरडीओ मुख्य रूप से रक्षा संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित करता है लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रौद्योगिकी अनुसंधान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा, इस तरह डीआरडीओ और एकेडेमिया के बीच साझेदारी होगी, तो डीआरडीओ दोहरे इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी के विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यह साझेदारी जितनी बढ़ेगी उतने ही अनुपात में भारत का रिसर्च सेक्टर भी बढ़ेगा। दोनों क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को व्यक्तिगत स्तर और संस्था के स्तर पर भी जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हैं, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है, कि देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर उन्नत सेना हो। भारत जैसे देश के लिए तो यह इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, हमारा प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण में उन्नत होना बहुत आवश्यक है। भारत कह्वादीआरडीओह्वडीआरडीओवहुत लंबी यात्रा तय करनी है। इसलिए सबका साथ चलना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा, 21वीं सदी भारत की सदी है, इसलिए 21वीं सदी में हमारे सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने में डीआरडीओ–एकेडेमिया साझेदारी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। यह साझेदारी भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी।ह्व रक्षा मंत्री ने कहा कि आज देश के सामने कई बड़ी–बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कोई संस्थान अकेले नहीं निपट सकता। इनसे सामूहिक प्रयास और साझेदारी से ही निपटा जा सकता है।

शरद पवार से मिले केजरीवाल, रजनीतिक हालात पर की चर्चा

प्रातः किरण

मुंबई/नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुंबई में मुलाकात की। इन नेताओं के बीच प्रशासकीय अधिकारी बदली अध्यादेश सहित देश की वर्तमान राजनीतिक हालत पर भी चर्चा हुई। इसके बाद तीनों नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर हमारा प्राथमिकता रहेगा। अगर संसद में प्रशासकीय अधिकारी बदली अध्यादेश आता है तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी और अरविंद केजरीवाल को समर्थन देगी। शरद पवार ने कहा कि इस समय देश में स्थिति बहुत ही विकट है। केंद्र सरकार हर जगह हस्तक्षेप कर रही है। देश में लोकशाही पर आघात हो रहा है। लोगों के मताधिकार को अबाधित बनाए रखना आवश्यक हो गया है। दिल्ली में जो हो रहा है, यह केवल दिल्ली की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की है, इसलिए वे विपक्ष को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार आने के बाद ही उनके अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया था। इसके बाद वे कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। आठ साल बाद सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने 11 मई को इसमें से एकमत से उनके पक्ष में निर्णय दिया लेकिन केंद्र ने 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को न मानते हुए अधिसूचना जारी कर फिर से चुनी हुई सरकार के प्रशासकीय अधिकारियों की बदली का अधिकार छीन लिया।

संबोधन — तीन देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर पीएम का जोरदार स्वागत

हर पल का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए किया : पीएम मोदी

प्रातः किरण/ एजेंसी

नई दिल्ली। तीन देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अपनी छह दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने हर पल का इस्तेमाल भारत की भलाई के लिए किया। इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं और समर्थकों ने यहां प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पालम हवाई अड्डे के बाहर अपने स्वागत के लिए एकत्र हुए लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सिडनी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान न केवल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और देश की सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी बल्कि एक पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने लोकतांत्रिक आत्मा और ताकत के इस प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, यह लोकतंत्र का माहौल था कि हर कोई भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि सभी ने भारतीय प्रतिनिधि को सम्मान दिया और यह मोदी के गौरव के बारे में नहीं, बल्कि भारत की ताकत के बारे में था। मोदी ने कहा कि वह विदेशों में भारत और यहां के लोगों की ताकत के बारे में आत्मविश्वास से बोलते हैं और दुनिया सुनती है क्योंकि यहां के लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के नेता जानते हैं कि वह जो कहते हैं वह भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के सामने अपनी जड़ें मजबूत करने की चुनौतियां हैं। साथ ही भारत नई ऊंचाई पर पहुंचने की दिशा में भी काम कर रहा है जैसा कि दुनिया उससे उम्मीद करती है। उन्होंने कहा, चुनौतियां बड़ी हैं। लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। उन्होंने उत्साहित भीड़ के सामने विश्वास जताया कि उनकी सरकार समय रहते इन उम्मीदों को पूरा करने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल

देश से वैश्विक उम्मीदें बढ़ रही हैं। मोदी ने यात्रा के दौरान प्रशांत द्वीपीय देशों के लोगों द्वारा दिए गए सम्मान के बारे में बात की और कहा कि महात्मा के दौरान उन्हें भेजे गए कोविड–19 टीकों के लिए इन देशों ने भारत के प्रति आभार भी जताया। विदेशों में टीके भेजने के सरकार के फैसले की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिए, यह बुद्ध की भूमि है, यह गांधी की भूमि है। हम अपने दुश्मनों की भी परवाह करते हैं, हम करुणा से प्रेरित लोग हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भारत की कहानी सुनने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपनी महान संस्कृति और परंपराओं के बारे में बोलने समय कभी भी गुलाम मानसिकता से पीड़ित नहीं होना चाहिए और इसके बजाय साहस के साथ बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह कहते हैं कि हमारे देश के तीर्थ स्थलों पर कोई भी हमला स्वीकार्य नहीं है तो दुनिया भी इससे सहमति व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि सिडनी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान न केवल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य मौजूद थे, बल्कि एक पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती रेखांकित करते हुए कहा कि यह भारतीयों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश भर में आयोजित 150 से अधिक बैठकों में जी–20 प्रतिनिधियों के भारत में हुए स्वागत ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, मैंने जिन नेताओं और अन्य लोगों से मुलाकात की, वे भारत द्वारा जी–20 की अध्यक्षता इतनी शानदार तरीके से किए जाने को लेकर बहुत मंत्रमुग्ध थे और सभी ने इसकी सराहना की है। यह सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन का किया शुभारंभ

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का गुरुवार को शुभारंभ किया और कहा कि यह ट्रेन इस देवभूमि के लिए भव्य उपहार है जिससे राज्य की चहुंमुखी प्रगति को रफ्तार मिलेगी। श्री मोदी ने यहां देहरादून रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिरकत की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में रेलवे के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक और महापौर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, उत्तराखण्ड के सभी लोगों को वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत–बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली–देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा।